

ASSENT TO BILL

SECRETARY: Sir, I lay on the Table the Copra Cess Bill, 1979 passed by the Houses of Parliament during the current session and assented to since a report was last made to the House on the 20th February, 1979.

12.03 hrs.

[MR. DEPUTY-SPEAKER in the Chair]

MR. DEPUTY-SPEAKER: Calling attention, Dr. Baldev Prakash.

SHRI EDUARDO FALEIRO (Mormugao): On a point of order. Mr. Kosygin had detailed talks with our Prime Minister and he left New Delhi two days ago . . . (Interruptions). You should direct the Prime Minister to make a statement regarding this.

MR. DEPUTY-SPEAKER: That is not a point of order.

CALLING ATTENTION TO MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

REPORTED MALTREATMENT OF REPRESENTATIVES OF PEOPLE'S UNION OF CIVIL LIBERTIES, SINGHBHUM

DR. BALDEV PRAKASH: (Amritsar): I call the attention of the hon. Minister of Home Affairs to the following matter of urgent public importance and request that he may make a statement thereon:

"Reported maltreatment to the representatives of the People's Union of Civil Liberties from Delhi visiting Singhbhum district on Wednesday, the 7th March 1979 to enquire into the complaints of violation of human rights of Adivasis of Singhbhum district and widespread resentment among the people."

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS AND IN THE MINISTRY OF LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS (SHRI S. D. PATIL): Sir, a team of

the People's Union of Civil Liberties from Delhi comprising of :

- (1) Prof. Dilip Swamy, Head of the Department of Business Economics, Delhi University,
- (2) Shri Soman Dube, Journalist,
- (3) Shri George Mathew, Research Scholar, Jawaharlal Nehru University,
- (4) Shri Anjan Ghosh, Lecturer, IIT, Delhi,
- (5) Dr. Arvindo Ghosh, K. M. College, and
- (6) Shri Ashok Kumar Panda, Advocate, Supreme Court,

visited Baharagora Police Station area on 7-3-1979 to enquire into alleged atrocities committed on agricultural labourers living in the jurisdiction of Baharagora Police Station. There was no advance information about their visit to this area. The team visited village Oida and contacted Shri Karunakar Mahapatra who entertained them to a cup of tea. The members of the team were accompanied by Shri Prasoon Goswamy and Shri Dalip Paul, alleged Naxalite workers of the area.

While the members of the team and the alleged Naxalites were leaving the village, Assistant Sub-Inspector K. B. Rai posted at Naya Basan outpost intercepted them, suspecting them to be Naxalites he demanded that they identify themselves. He appears to have treated them roughly although Prof. Dilip Swamy had disclosed their identity and produced the letter he carried from Shri Tarakunde addressed to the Chief Minister, Bihar. The Assistant Sub-Inspector took them to Naya Basan police camp at about 5.30 p.m. and kept them there until the Circle Inspector of Baharagora arrived with a police party at the Police Camp at about 8 p.m. A crowd had collected by that time and presumably on being told that the party contained Naxalites, attacked it while it was being

[Shri S. D. Patil]

taken in a vehicle to the Baharagora police station. Some members of the party suffered injuries as a consequence of this attack. The party appears to have been kept in the Police Station till 3.00 A.M. on 8th March, 1979.

The members of the party were arrested on a complaint of trespass lodged by Shri Karunakar Mahapatra at Police Station, Baharagora and released on personal bonds thereafter. This was the same Karunakar Mahapatra whose house the members of the team had visited at village Oida and who had entertained them to a cup of tea.

An offence under section 143/341/323 IPC was registered at police station, Baharagora on a complaint lodged by Prof. Swamy alleging assault and confinement by Assistant Sub-Inspector Rao, police constables and members of the public. 20 persons have been arrested so far in this case.

The members of the team who had received injuries could not be treated at Baharagora Police Station as the local doctor refused to examine them at night. However, they were rendered First Aid by the thana officer and the Circle officer. Injuries were attended to at Government hospital, Jamshedpur, later.

On receipt of information about the incident, S. P. Singhbhum and S.D.O. Jamshedpur visited the place of occurrence to conduct enquiry. Assistant Sub-Inspector Rai has been suspended. Government of Bihar have directed the Commissioner Ranchi and DIG of Police, Chhota Nagpur range to conduct a joint enquiry. Enquiry report is awaited.

श्री ० बलराम प्रकाश उपाध्यक्ष महोदय, जो राज्य मंत्री महोदय से सदन के सामने बयान दे चुके हैं, मैं उन से कुछना चाहता हूँ कि क्या वे स्वयं इस बयान के संकट हैं? जो स्टेटमेंट था था है उसके पक्ष में

(१०)

ही पता लग जाता है कि इस में किंगी बम्बेजियों के साथ किंगी वेक्यूमिबार्ड बार्डों लिखी हुई है। इस में नहीं भी वे बताया है कि ६ व्यक्तियों का एक गिफ्टमंडल बना गया। वहाँ भी कप्तानकर महापात्र से उलझे फटे-पटे कपड़े और उसने उस गिफ्टमंडल की वेक्यूमिबार्डों की, उसने गिफ्ट मंडल को चाय भी पिलायी। फिर उसी महापात्र की कम्प्लेंट पर ही उनको अरेस्ट किया गया। यानी यह स्टेटमेंट इस सदन के सामने था था है। फिर इस में यह कहा गया है कि उनके साथ नक्सलाइट्स से और जब वे वहाँ प्राये तो पुलिस के सब इन्स्पेक्टर ने उनको गिफ्ट कर लिया। उनसे प्राइवेटिटी वेपरस मांगे गये। उनके पास पीपुल्स मूविंग्स आफ सिविल लिबरटीज के श्री तारकुम्हे साहब का नोटबूट बा जो कि बीक मिनिस्टर के नाम लिखा हुआ था। यह नोट देखने के बाद भी क्या कारण है कि वहाँ की पुलिस ने उनको हिरासत में रखा?

उपाध्यक्ष महोदय, इतना ही नहीं घाट बजे वहाँ सर्फिस इन्स्पेक्टर भी था गया और उसके घाने के बाद उसने सारी चीजें देखी होगी और वह लेटर भी देखा होगा और तीन बंटे उन्हें हिरासत में बैठे हुए भी हो गये थे, फिर क्या कारण था कि सर्फिस इन्स्पेक्टर ने कोई कार्यवाही नहीं की और सुबह तीन बजे तक उनको हिरासत में रखे रखा?

उपाध्यक्ष महोदय, स्टेटमेंट में यह भी कहा गया है कि जब जनता को यह पता लगा कि इसमें कुछ नक्सलाइट्स हैं तो लोग वहाँ इकट्ठे हो गये और उनको बारने लग गये। क्या वहाँ यह कानून व्यवस्था है? अगर कहीं नक्सलाइट्स हैं, और उनको होने का आरोप भी ठीक हो तो क्या जनता को इस तरह का व्यवहार करने का हक है? ये नक्सलाइट्स क्या हैं? ये देश में प्राथिक विषमता के कारण उत्पन्न हुए हैं। यह एक समस्या है जिसको हल करना होगा। नक्सलाइट्स कोई जिजीव्य नहीं हैं, यह हमारे देश की सोशो-इकोनॉमिक कंडीशन का परिणाम है। ये कोई देशद्रोही नहीं हैं कि इनको गोली मार दी जाए। ये नक्सलाइट्स से इसलिए इनको मार दिया जाए जैसे कि एमजेंसी के समय ऐसा हुआ करता था।

उपाध्यक्ष महोदय, इतना ही नहीं, डा० ने उनको देखने से इंकार कर दिया। यह डाक्टर कौन का? यह सरकारी डाक्टर था या प्राइवेट डाक्टर था? अगर वह सरकारी डाक्टर था तो उसने कैसे इंकार किया कि वह उस के समय उनको नहीं देखेगा? हो सकता है कि उसने कुछ सीरियसकी इन्वर्स हों। क्या डाक्टर के खिलाफ कोई कार्यवाही की गयी कि उसने उन्हें देखने से इंकार क्यों किया?

मैं यह जानना चाहता हूँ कि यह जो बयान सदन के सामने था था है, इसका यह जर्म नहीं होना चाहिए कि यह कुछ का पुलिसवा हो। फिर उसके से वहाँ पर विचार है, पीके सुनील कोठे के अन्दर यह बयान था जो कि बलराम प्रकाश के अन्दर उपाध्यक्ष वहाँ बंध हैं और पुलिस के सुन-बार्ड-बार्ड तक सफ़ाई

नहीं किने हैं। उन्ही तरह की यह एक चीज है। वह पुलिस राउट का नमूना है। इस चारे बन्तव्य में जो बुझक डोडाला है क्या मंत्री महोदय उससे संतुष्ट हैं और अगर संतुष्ट नहीं हैं तो क्या वह अपने वीर पर एक लिप्यक्ष बांध समिति बिडाने के लिए तैयार हैं? पुलिस के अफसरों ने कथ्याकर महापाल से दरबारात लिखाई, लोगों को इकट्ठा कराया, वहाँ पर उनकी पिटाई की गई, उनको हिरासत में रखा गया, उनको वहाँ बाँटे सभी कनपूषुव में, किसी की बाँध के नीचे बाँट लगी और किसी को साठी से बाँट लगी, क्या इस सब की जांच करवाने के लिए वह तैयार हैं? मैं जानना चाहता हूँ कि उन के खिलाफ क्या कार्रवाई की गई है? इन सब बातों को देखते हुए क्या मंत्री महोदय विचार करेंगे कि केन्द्रीय सरकार की तरफ से कोई हार्ड सेवेस, उच्च स्तरीय जांच समिति बिठाई जाए जो वहाँ पर जा कर आदिवासियों पर हो रहे अत्याचारों की जांच करे और सारी बैकग्राउंड में जाए और सिविल लिबर्टीज के जो प्रतिनिधि वहाँ गए थे उनके साथ हुए दुर्व्यवहार की जांच करे? अगर देश में यही हाल रहा तो फिर मैं कहना चाहता हूँ कि देश में नागरिक स्वतंत्रता कहीं नहीं रह पाएगी। उन पर अत्याचार हो रहे थे और अगर दिल्ली से कोई देखने के लिए गया तो उनको भी इनाम मिला और कहा गया कि आप देखने के लिए आए हैं क्या अत्याचार हो रहे हैं, जो आप भी बोझा सा सैम्पल लेते जाइये उसका जो वहाँ पर अत्याचार हो रहा है। मैं जानना चाहता हूँ कि कोई हार्ड सेवेस जांच बिडाने के लिए क्या केन्द्रीय सरकार तैयार है जो सारी घटनाओं की जांच करके रिपोर्ट दे और जो दोषी व्यक्ति हैं, पुलिस इंस्पेक्टर और डाक्टर जिन्होंने कार्रवाई नहीं की, क्या उनके खिलाफ आप कोई एकजन सेने के लिए तैयार ह? ?

SHRI S. D. PATIL: There are one or two specific points which the hon. Member has raised. There is no question of my subjective satisfaction about the statement itself. The statement is based on the information supplied by the State Government. The question of arrest at the instance of Shri Karunakar Mahapatra may turn out to be something which was a hoax; one cannot say at this stage, because the State Government has already appointed a Committee. As far as action against the police ASI is concerned, he is already under suspension. About the doctor, it appears that he is a local doctor. Government have no information whether he is a private or Government doctor. Because of the pressure that was mounting there, he could not give medical assistance, the local situation developed in such a manner. Suppose he was a Government doctor, at the risk

of his life, he should have treated them because these are all responsible and respectable people. As regards detention from 8.30 to 3 a.m. for nearly 7 hours, only the enquiries will reveal whether this was justified or not and under what circumstances the ASI was compelled to keep them; may be it was in order to give them protection from the fury of the masses; one cannot say.... (Interruptions). There was an agitation mainly among the agricultural labour to demand minimum wage. The objective is laudable but it has taken a wrong turn. This has got some relation to the incidents which happened on the 25th November 1978.

श्री विनायक प्रसाद यादव (सहरसा) : जो रिपोर्ट मंत्री महोदय ने पढ़ कर सुनाई है उसके बारे में माननीय सदस्य ने कहा कि यह झूठी है। रिपोर्ट में लिखा हुआ है :

"The team visited village Oolda and contacted Shri Karunakar Mahapatra who entertained them to a cup of tea."

उसके बाद वहाँ बातचीत होने के बाद :

"While the members of the team and the alleged Naxalites were leaving the village, Assistant Sub-Inspector K. B. Rai posted at Naya Basan outpost intercepted them, suspecting them to be Naxalites.."

मंत्री जी ने अभी कहा हो सकता है कि उनकी सुरक्षा के लिये इनको रोका गया हो। लेकिन रपट से स्पष्ट है कि गाँव में इनकायरी कर के श्री महापाल ने उनको बाय पिलायी, पूरी बात हुई और जब उस गाँव से टीम बच बी तो रास्ते में ए०एस०आई० ने उनको पकड़ कर रीजुल कनफ्रानमेंट किया। रपट में है कि आदिवासियों पर हो रही ज्यादतियों की जांच के लिये यह लोग गये थे। वो, तीन महीने से वहाँ का सिचुएशन बहुत ऐक्सप्लोसिव है। 8 नवम्बर, के "धर्मव्रत" अखबार में छापा है कि पुलिस की गोली से एक आदिवासी मरा। इसी अखबार के 18 नवम्बर के संस्करण में छापा है कि पुलिस की गोली से एक मरा और वो घायल हुए। इसी तरह 14 नवम्बर, के "भाज" अखबार में निकला है कि बेगाबाब भानान्त मध्यासीह अन्धकार में परसों पुलिस ने आदिवासियों की हिसक कीड़ पर गोली चलायी। यह बटना अबरक ज्ञान के मालिक की खमीन पर धान काटने को ले कर हुई। "धर्मव्रत" के 27 नवम्बर, के संस्करण में छापा है कि

[श्री विनायक प्रसाद यादव]

पुलिस की गोली से तीन भादिवारियों की मृत्यु हुई। मतलब यह कि वहाँ पर 2, 3 महीने से पर्यटक गोलीकांड हो रहा था, और उसके बाद सिविल लिबरटीज वालों को खबर गई तो वहाँ से यह जांच के लिये गये थे। और फिर जांच करने वालों के साथ जो घटना हुई वह आपके सामने है।

आप देखें कि समूचे देश के अखबारों में क्या निकल रहा था, जैसे "हिन्दू" अखबार में है कि :

"Where Violence is a Way of Life, Killing has become routine, murder a legitimised vocabulary of retaliation in Bihar. It is all a question of survival, say those involved in it."

इसी तरह से "टाइम्स आफ इंडिया" में है :

"Concern at lawlessness in Bihar."

"डैकन हेराल्ड" में है :

"Police difficulty in maintaining law and order".

"इंडे" अखबार में है :

"The pahalwans, police and the public sector management form a league of criminals which rapes women and steals money."

इस तरह से दो, तीन महीने से यह घटनायें हो रही हैं और लगभग 400, 500 भादिवारियों वहाँ मारे गये हैं। तो अब इतनी पुरानी घटना है और ऐकसन्तोसिव सिन्चुएशन है तो क्या गृह मंत्री महोदय वहाँ गये हैं जांच के लिये ?

भूसा सवाल यह है कि भारतीय संविधान के मूलाधिक केन्द्र में परमानेंट सैड्यूल्ड कास्ट्स और ट्राइब्स के लिये कमीशन बना हुआ है। वो, वो गृह राज्य मंत्री हैं, क्या उनमें से कोई भी भादिवारियों की हालत को देखने के लिये गये ? नहीं तो एक कमीशन है जिस पर हजारों ४० महीने खर्च हो रहा है, क्या सैड्यूल्ड कास्ट्स कमिश्नर को आपने वहाँ पर भेजा भादिवारियों पर ही रहीं ग्यावर्तियों को देखने के लिये ? यदि हाँ, तो उनकी क्या रिपोर्ट है ?

तीसरा सवाल यह है कि ला एंड आर्डर और सिविल लिबरटीज के मामले पर दो महीने पीछे बिहार के राज्यपाल ने इस्तीफा दिया क्योंकि वहाँ कोई ला एंड आर्डर नहीं है, कोई देखने वाला नहीं है। हालांकि वहाँ एक मिनिस्ट्री है, उसके बावजूब भी गवर्नर को ला एंड आर्डर के लिये पीटिंग बुलानी पड़ी और अब भीटिंग बुलानी तो उन पर चारों तरफ से हमला हुआ। अन्त में यह उम्ह कर के इस्तीफा द कर के साथ गये।

तो एक गवर्नर एक स्टेट में कोई ला एंड आर्डर नहीं है उस पर इस्तीफा देता है, इतने अवाज्ज कांड होने के बाद भी क्या गृह मंत्री जो ने बिहार के बारे में वहाँ के भादिवारियों और हत्याओं पर जो चुप्पे हुआ है उसके बारे में कोई कार्यवाही की है कि नहीं ?

मेरा चौथा प्रश्न यह है कि 8 नवम्बर को प्रावरित हुई, 18 नवम्बर को कार्यालय हुई, हर कार्यालय में, वो, श्री भादिवारियों मारे गये हैं। 14 नवम्बर को प्रावरित हुआ है, उसमें भी 3 भादिवारियों मारे गये हैं। इस तरह से तो लगातार कार्यालय होता रहा है और वर्षों भादिवारियों पुलिस द्वारा गोली के बात उतार दिये गये, तो मैं सरकार से जानना चाहता हूँ कि जितने भादिवारियों 2, 3 महीने में पुलिस द्वारा गोली से मरे हैं उनके बालबच्चों के लिये सरकार ने क्या मुआजजा दिया है और क्या कार्यवाही की है ?

मेरा अंतिम सवाल यह है कि बिहार जल रहा है, कोई ला एंड आर्डर वहाँ नहीं है, इसलिये मैं यह जानना चाहता हूँ कि यह जो इतनी घटनाएँ वहाँ हुई हैं, क्या भारत सरकार इसके लिये तैयार है कि इस सब कार्यालय की ज़िम्मेदार इन्कवाररी करवा ले ? सिविल लिबरटीज के लोगों के साथ जो जुल्म किया गया है, किस तरह से उन्हें बेइज्जत किया गया है, इसका टेपरिकार्ड कर के साया गया और श्री जयप्रकाश नारायण जी को टेपरिकार्ड सुनाया गया, जिसे सुनकर उनकी आंख से आँसू गिरने लगे और उन्होंने कहा कि इससे ब्यादा जबरन अपराध कोई नहीं हो सकता, तो मैं उपाध्यक्ष महोदय, आपके अरिये यह पृष्ठना चाहता हूँ कि क्या इन सब जुल्मों की जांच के लिये इस माननीय सदन के सदस्यों की कोई कमेटी बनाने के लिये सरकार तैयार है ?

SHRI S. D. PATIL: The incident on 7-3-79 is not doubt regretted. But all the criticisms that have been levelled by my hon. friend from Bihar are against the State Government. It is for the State Government to take adequate notice of what has been said here

श्री विनायक प्रसाद यादव : आप क्या कर रहे हैं ?

श्री मोहन जाल पिपिल (बुर्बा) : उपाध्यक्ष महोदय, जब यह केन्द्र से संबंधित नहीं है तो मंत्री महोदय क्याम क्यों दे रहे हैं ? उनको तो कह देना चाहिये कि राज्य सरकार के पास चाहे।

SHRI S. D. PATIL: I do not want to comment one way or the other. Subsequently, it appears, Mr. Karunakar Mahapatra who entertained a cup

of tea at village Olda to all the six members of the People's Union of Civil Liberties, has also lodged a complaint . . .

श्री श्रीधर साहू विदितः देखिये हम लोगों के साथ जोर बर्बरता है, हरिजन और प्राविदारियों के साथ यह बोकावड़ी है।

MR. DEPUTY-SPEAKER: Please don't get emotional. The hon. Member has put a question, let the Minister reply to that.

SHRI S. D. PATIL: Mr. Karunakar Mahapatra appears to have lodged a complaint against the same persons. It has now come to light that he has also done it in the interest of the landlords. This is the information which I have received. May be, he might have been driven to lodge a complaint against these people.

As far as the paper reports regarding the atrocities committed against Adivasis are concerned, there was already an Unstarred Question on 1-2-79 raised by Mr. A. K. Roy who represents that area on the number of Adivasis killed in police firing in Chhota Nagpur in Bihar during 1978; the names of Adivasis killed; the facts, details and cause of firings. If the hon. Member wants, I can read out the reply. There were five Adivasis killed—three were Maheshwar Janoda, Lupa Munda and Somanath Longa, fourth and fifth were unidentified. The place where the incident took place is Simdega, District Ranchi. I read the reply:

"On 3-8-78, about four thousand Adivasis surrounded Simdega jail, attached the police party and caught hold of the Jailor. The Magistrate on the scene was injured. The mob failed to disperse on warning. Firing was ordered as a result of which one unidentified person was killed."

"(i) Place—Village chahatu, District Singhbhum, Date—6-11-1978:

An unlawful assembly of about 1,000 armed persons defied prohibitory orders under Section 144 Cr. P. C. and threatened to blow up the bridge over Goelkara-

Chaibasa Road. They also threatened to cut down teak wood trees in Santara forest range. Seven leaders were arrested for violating prohibitory orders. The mob became violent and came forward for the rescue of arrested persons. Warnings, followed by lathi-charge proved ineffective. The mob surrounded the police parties resulting in imminent threat of arms being snatched from the police. The lives of the police party were in imminent danger...'

"(iii) Place—Village Serengda, District Singhbhum. Date. 25-11-1978.

A police patrol party arrested one Shri Shailendra Mahto, who was accused in cases of illegal felling of trees. The arresting party was attacked by about one thousand armed persons, injuring 11 policemen and the accompanying magistrate. Firing was resorted to, to protect the lives of the patrol party. Three persons S/Shri Lupa Munda, Somanath Longa and one unidentified person were killed."

As far as a judicial probe from here is concerned, the Bihar Government is controlled by a Party, there is a regular Government there. The Central Government cannot come in.

As far as appointment of Committee of the House is concerned, again there is the same consideration. So long as there is an inquiry and the report is awaited, it will be too early to consider that proposition.

About reference of this matter to the Scheduled Castes and Scheduled Tribes Commission, this question can be considered because on an earlier occasion the Prime Minister has also referred certain questions. But it is a matter at what stage it should be referred to them, whether they are willing or not, we have to ascertain; we have to ascertain the willingness on their part whether they will go into

[Shri S. D. Patil]

all these complicated questions or not. After the Inquiry Report is received, we may think about the advisability or other wise of that.

श्री बिनायक प्रसाद यादव : उपाध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने मेरे एक सवाल का जबाब नहीं दिया है। सिद्धयुक्त कास्ट्रस कमीशन को तो वरीर सरकार से पृष्ठ, जहाँ से रिपोर्ट मिले, वहाँ जाना चाहिए। क्या वह वहाँ गया है या नहीं ?

MR. DEPUTY SPEAKER: He has already replied to that question.

श्री कंवर लाल गुप्त (दिल्ली सदर) : उपाध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने वहाँ पर बायलेस होने के बारे में जो बाले बताई हैं, अगर वे सब बाले ठीक हैं, तो बायलेस को तो मैं कभी भी स्वीकार नहीं कर सकता हूँ—मैं उसको ब्रम्हा नहीं कहूँगा। लेकिन उन्होंने जो बयान दिया है, ऐसा लगता है कि वह एक कुबड़ स्टोरी है। There is a clear connivance, conspiracy, of the police with the landlord and the officials. It is a clear case of conspiracy, according to your own statement. इन लोगों को बैजीएस के साथ पीटा गया, और वहाँ पर जो पाप किये गये थे, उन पर पर्दा डालने की कोशिश की गई, ताकि झाँड़ा कोई को एनक्वायरी करने चाये ही न। It is an insult to all of us who believe in the rule of law, to the whole House. After all, we fought against authoritarian rule. We fought for the rule of law, and even in our Government we sometimes see that, here and there, there are cases where rule of law is completely violated. I must say that it is a case of barbarous attitude of the Police, and you cannot treat it in a shabby way saying, 'This is the State Government's function; I cannot interfere in that'. Agreed, strictly speaking, according to the Constitution, this is a State subject. But certainly you can advise the State Government. The State Government is our Party Government. Do you think that what happened in Bihar will not affect Delhi and other parts of the country? It will affect.

Therefore, this Government should see to it that the rule of law prevails everywhere in the country and where it has broken down, the Central Gov-

ernment should take action or at least ask the State Government to take action. जो आप ने एनक्वायरी को बाल कही, कौन एनक्वायरी करेगा? डी० आई० जी० साहब करेंगे। जो पुलिस के ही कर्मचारी हैं वह पुलिस के ही खिलाफ एनक्वायरी करने जिन्होंने कि कांसपिरेसी की।

The accused and the magistrate are the same person. Can you think that it will create confidence in the minds of the public and the poor tribals? May I request the Minister that this inquiry cannot create confidence in the minds of the people there or in the minds of the Members of this House. If you want to do something and not interested in white-washing, then you must ask the Chief Minister to institute an independent inquiry. I do not suggest a judicial inquiry, but, certainly I would like that it should be an independent inquiry, an inquiry independent of the Police. Secondly, it should be a comprehensive inquiry, comprehensive enough to include all the incidents as referred to by my hon friend, which I do not want to repeat. For 2 to 3 months this thing has been going on. Were they Naxalites? If they are what are their demands? I know they want land, they want job in the public sector. They are poor people. They want wages. The economic aspect should also be looked into. I am sorry that aspect cannot be dealt with by the DIG. Therefore, a comprehensive inquiry including this incident, including what happened in the last 2-3 months should be held by a competent and independent authority.

उपाध्यक्ष महोदय, मेरा कहना यह है कि जो यह महापाल साहब हैं, आप ने खूब ही कहा है कि ये लैड सार्जिस के साथ में हैं, लैड सार्जिस से मिल गए। पहले तो बाय पिला दी इन को फिर एनक्वायरी करा दी। यह बिल्कुल कमीशर है कि उन का एक आई० डार० फाल्स है। तो उनके खिलाफ आप क्यों नहीं कार्यवाही करते? जो मैजिस्ट्रेट वहाँ पर थे, एस० डी० एम०, उन को खिलाफ कार्यवाही क्यों नहीं करते? फाल्स कम्प्लेंट करना भी जूम है। तो जो पुलिस के कहने से यह सब कुछ किया और जिन्होंने पिटाई की पुलिस की मौजूबी में— These people were in the custody of the Police and they were beaten. I

think that never happens in any civilised society.

एक तरह से लगता यह है, आप अपने बयान में देख लीजिए, ऐसा लगता है कि इनको से बताया गया और पिटवाना गया। यह जो आप का कहना है कि उन को बचाने के लिये ले जाया गया, नहीं, उन को पिटवाने के लिये वहाँ इकट्ठा किया और जितने लैब्सार्डस थे, जितने वैसे वाले थे, कम्पनी वाले थे, अफसर थे, कारेट के आफिसर्स थे, उन सब ने मिल कर के यह किया। वहाँ उन की पिटाई अच्छी तरह हुई।

सब से बड़ी दुःख की बात यह है कि [जयप्रकाश जी जैसे आदमी ने इस पर शोक प्रकट किया है, उन का कहना है कि उन की भाँषों में प्राप्ति भी प्राण। तो क्या यह सरकार जिस ने देश की बीबाना आजादी के लिये एक मार्ग लड़ाई का नेतृत्व किया वह यह करेगी कि सी०आर०सी० फैसला करेगा। क्या यही कीमत आप के पास है? मैं नहीं समझता कि पटेल साहब या पाटिल साहब इसके बारे में ऐसा फ्लैस ऐटीच्यूड लेंगे? वह मामला गंभीर है। आखिर मैं सिंबल लिबर्टीज यूनिनन यहाँपर काम करती है, कल को हम लोग भी एन्क्वायरी करने जाते हैं, आप जी जाते हैं, सब लोग जाते हैं, अगर सब के साथ वही हाल हुआ तो क्या होगा? आप भी मुंबयफरनगर गए थे। आप तो भायद मंत्री है नहीं कुछ हुआ होगा? लेकिन अगर कोई एम०पी० गए और उन के साथ भी ऐसा ही हुआ तो क्या होगा? तो इस तरह के एन्सीडेंट न हों, उस के लिए आप बिहार सरकार को कहिए। मैं गृह मंत्री जी से कहना चाहूँगा कि अगर इस तरह से बारबेरस ऐक्शन हुए तो इस देश के लोगों ने भीत महीने जी लड़ाई लड़ी, उसकी कोई कीमत नहीं रह जायेगी।

मैं माननीय मंत्री जी से पृथना चाहता हूँ क्या आप

(1) Comprehensive enquiry into all the incidents by an independent authority;

Will you recommended this to the Bihar Government? That is No. 1.

दूसरे, जो महापात्र साहब हैं, जिन्होंने पहले बयान पिसाई और फिर झूठी कान्टेक्ट की, क्या उन के खिलाफ कार्यवाही की जायेगी? और एम० सी० एम० के खिलाफ कार्यवाही होगी या नहीं? इस के अलावा जिन्होंने अटैक किया पुलिस कस्टडी में, वहाँ जितने पुलिस वाले थे और कले वाले थे, उन के खिलाफ क्या कार्यवाही होगी?

तीसरी बात यह है, कि धर्मो जी प्रान्णम है बेकेस की, टोटी की, जमीन की, उसको साल्व करने के लिए आप क्या कर रहे हैं?

चौथी बात यह है कि जो लोग मरे हैं उनको क्या आपने कम्पेन्सेशन दिया है? जैसा मैंने पहले

कहा है, जो बायसेल में इंडलज हुये हैं उनके साथ मेरी कोई सिम्पैथी नहीं है

I condemn violence with all my emphasis at my command. I am not supporting this.

मैं चाहूँगा कि गृह मंत्री जी इन बातों का जबाब दें। इस मामले को सेबीली ट्रीट न किया जाये। क्लम आफ ला, जिस पर जनता पार्टी बड़ी है, उस का वास्तविक समूत सरकार दें। (Interruptions).

AN HON. MEMBER rose.

MR. DEPUTY-SPEAKER: I am sorry, only those names which appear in the notice will be allowed. You cannot get up like this. Hon. Minister.

THE MINISTER OF HOME AFFAIRS (SHRI H. M. PATEL): Sir, I would like to say this that the hon. Member wants that everything should be done according to rule of law. I would certainly say that I am in entire agreement. He must, therefore, realise that this is a State subject. When a Call Attention Notice of this kind has come here, the duty here of the Central Government would be to tell you the facts on the matter that has been brought before us for our attention.

This does not mean that we either approve of it or disapprove of it. You will see that this is a mere narration of the facts. When my hon. colleague replied, he pointed out that this is a report received from the State Government (Interruptions). The call attention is with respect to this particular incident and the members of the Civil Liberties' Union's going there and the matter being handled in a particular manner. It is certainly very deplorable. But we shall certainly give the advice and ask the State Government to go deeply into the matter. That is the only thing that can be done at this stage. I am sure, my hon. friend, will appreciate that it is only after a proper enquiry that we can... (Interruptions).

SHRI KANWARLAL GUPTA: How will you take anyone into confidence?

SHRI H. M. PATEL: That is why I said that we shall pass on the views

[Shri H. M. Patel]

that you have expressed here plus what all advice we can give, which, you consider, is called for.

श्री वसुधा प्रसाद शास्त्री (रीवा) : धनी मालगीय गृह मंत्री जी ने जो उत्तर दिया उस से ऐसा लगता है कि इस घटना की गम्भीरता को वे भी कम फरके धाक रहे हैं, हलके ढंग में से रहे हैं। यह कहना गलत है कि यह सारा का सारा विषय राज्य सरकार से संबंधित है। जहाँ तक हरिजनों तथा आदिवासियों का प्रश्न है, केन्द्रीय सरकार की विशेष जिम्मेवारी है, यह हमारे संबंधित में स्पष्ट रूप से उल्लिखित है। भारतीय संविधान में इस के लिए स्पष्ट प्राविधान है कि आदिवासियों, हरिजनों एवं अन्य नीचकर सेव्यान्स की जिम्मेवारी केन्द्रीय सरकार की है। यह जो ध्यानाकर्षक प्रस्ताव रखा गया है वह केवल इतना ही नहीं है कि पीपल्स यूनिवर्सिटी फार सिविल लिबरटिज के प्रतिनिधियों के साथ मार-पीट की गई। प्राप कालिग प्रदेसन को पढ़िये, उस में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है।

“आदिवासियों के मौलिक अधिकारों के हनन की जो पश्चात्ताप थी उस की जांच करने के लिए वे लोग गए थे ...

श्रीर उनको साथ जो ब्यापार हुआ, मार पीट की गई, जिसके कारण एक ब्यापक भ्रष्टाचार है, “इसमें आदिवासियों की बात स्पष्ट कही गई है, इस लिये केन्द्रीय सरकार अपने जिम्मेवारी से मुह नहीं मोड़ सकती।

धन हमें देखना यह है कि कितनी विषय परिस्थिति है, कितनी लज्जानक स्थिति है। मैं पृथुना बाहता हूँ उस सिधभूम जिले में या बिहार के दूसरे जिलों में जहाँ आदिवासी रहते हैं—कोई सरकार है या नहीं? वहाँ भ्रष्टाचार की स्थिति है, आदिवासी बेचारे मांग करते हैं कि हम को मिनिमम वंज मिले, लेकिन वहाँ खेती में काम करने वालों को डेढ़ किलो, एक किलो या उससे भी कम भ्रष्टाचार मजदूरी के रूप में दिया जाता है। बिहार सरकार ने खेतिहर मजदूरों के लिये जो न्यूनतम मजदूरी कानून में निर्धारित की है—आदिवासी उसी के लिये मांग कर रहे हैं, किसान समिति इस को लिये वहाँ भ्रष्टाचार नला रही है, लेकिन उन पर गोलियां चलाई जाती हैं। श्रीमान, इतना ही नहीं, वहाँ जो पुराने जंगल थे, साल के, महुआ के, तैलू के, जिन से आदिवासियों का जीवन चलता था, उन को काट कर सीमान के वेड़ लगाये जा रहे हैं, जिस के विरोध में वहाँ के आदिवासी आवाज उठा रहे हैं। उन का कहना है कि सीमान से हम को क्या मिलने वाला है, महुआ से या तैलू का फल खा कर हम अपना जीवन चलावे हैं, लेकिन उन को बर्खास्त किया जा रहा है। उन की ग्याबोचित मांगों को सुनना तो दूर रहा, उल्टा उन पर गोलियां बरसाई जाती हैं और जो गोलियां बरसाते हैं उन को कुछ नहीं कहा जाता, उन के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं होती। क्या वहाँ की पुलिस आदिवासियों की हत्या के लिये है? ऐसी स्थिति में हमारे राज्य और हमारी पुलिस का क्या कर्तव्य है? ऐसी स्थिति में पुलिस को किस के पक्ष में जाना चाहिये, राज्य किस का उपयोग किस के संरक्षण के लिये होना चाहिये?

क्या राज्य प्रकृत का उपयोग उन लोगों के खिलाफ नहीं होना चाहिये जो मिनिमम वेज कानून का उल्लंघन कर रहे हैं, जो आदिवासियों की जीविका का हनन कर रहे हैं, जो आदिवासियों को मार रहे हैं—यै इस के बारे में केन्द्र सरकार का स्पष्ट कथाना चाहता हूँ? श्रीमान, गोलियां केवल पुलिस ने ही नहीं चलाई हैं, नवा बसन गांव के रघुनाथ सिंह खनीवार ने भी गोलियां चलाई हैं और उस की रिपोर्ट पुलिस में दर्ज है। लेकिन न रघुनाथ सिंह को पकड़ा गया और न उस के साथी गुप्ते पकड़े गये। उस वे जमशेदपुर से गुणों को बूला कर वहाँ गोलियां चलाई। वे इतने सभ्यता शीघ्र—दिल्ली विश्वविद्यालय के हेड—प्राक्-डिपार्टमेंट की दलीप स्वामी, जो अन्तर्राष्ट्रीय छात्रों के विद्वान हैं, उन के नेतृत्व में यह प्रतिनिधि मंडल वहाँ गया था। जस्टिस तारकूबे का पत्र लेकर गया था, जो श्री कर्पूरी ठाकुर के नाम था और जिस समय घोसला गांव से वे लोग निकल रहे थे, के० बी० राय ने पिस्तौल लेकर उन को रोका, दो पुलिस के सिपाही उस के साथ थे। उस ने जस्टिस तारकूबे को गोली दी, कर्पूरी ठाकुर को गोली दी, चौधरी बरण सिंह को गोली दी, श्री मोरारजी देसाई को गोली दी। वहाँ की पुलिस में इन लोगों के लिये कोई इच्छत नहीं है, कोई प्रतिष्ठा नहीं है, वे उन को खबरदारी पकड़ कर ले गये और उन से कहा—सुम सब को पुलिस की गोलियों से उड़ा देंगे। यह टेप-रिकॉर्ड उन के पास रखा है, प्राप उस को सुन सकते हैं, उन को हत्या की घमकी दी गई, रास्ते में उन को पीटा गया और फिर पुलिस कैम्प में ले जा कर पीटा। और फिर चारों तरफ से गुणों को खबर दे कर बुलवाया गया। यह बात वे गलत कह रहे हैं कि वे अपने प्राण इकट्ठा हुए। के० बी० राय ने उन तमाम गुणों को इकट्ठा करवाया और हमला करवाया। एक्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट जो थे, वे बाहरगोरा पुलिस स्टेशन से 8 बजे पहुंच जाते हैं। एक्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट को ये पत्र दिखाते हैं लेकिन वह सुनने को तैयार नहीं है। के० बी० राय झूठी बात कह देता है कि इन के पास बम है, पिस्तौल है। कोई देखता नहीं है कि उन बेचारों के पास सूई तक नहीं है और केवल जस्टिस तारकूबे का एक पत्र है। एक्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट कहता है कि इन को जीप में थाने से चलो और जब जीप में वे बैठ जाते हैं, तो एक्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट की उपस्थिति में, पुलिस की उपस्थिति में उन को पीटा गया। प्रो० दलीप स्वामी को लाठी से मारा गया और जो भी धमिये थोस हैं, जोकि एक प्रोफेसर हैं, उन की प्राण के नीचे से खून बहने लगा और उन को पुलिस थाने ले आया जाता है और 8 बजे से सत्रे 3 बजे वहाँ पर उन को रखा जाता है। श्री करणाकर का गांव घोसला नहीं है, यह प्राप का स्टेटमेंट गलत है। मैं पूरी जिम्मेवारी से कहता हूँ—प्राप ने हाऊस में यह झूठी बात कही है उस का घर घोसला में है—कि उसका घर घोसला में है। इस को प्राप करके जीए। यह उस गांव का रहने वाला है और उसको बूलाकर इन के सामने झूठी रिपोर्ट लिखाई गई। यह कहा जा चुका है कि हमारे साथ भ्रष्टाचार ब्यवहार किया है और वही टेप रिकॉर्ड में है। इन लोगों के सामने झूठी रिपोर्ट लिखाई गई और मुकदमा धर्ष किया गया इन के ऊपर लेकिन प्रो० दलीप स्वामी ने जो रिपोर्ट लिखाई उस का कहीं पता नहीं है। उस रिपोर्ट में

यह था कि हम को योबी से मारने को कहा और हम को रास्ते में मारा और मुम्बई में पिठवाया गया और हत्या का प्रचार किया गया। मैं पूछना चाहता हूँ कि के० बी० राव को केवल सशपथ क्यों किया गया। के० बी० राव को, एक्जीक्यूटिव मेजिस्ट्रेट को उन पुलिसवालों को गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया। यह मुकदमा सीखा सीखा है कि यह जो अपराध है, युष्म है, यह बड़ा भारी अपराध है। उन को केवल प्रारण से हटा दिया गया। इतनी देर तक उन को बैठा कर रखा गया। 342 का मुकदमा बैठता है। रॉगफुल कनफाइनमेंट, एटेंडेंट मजिस्ट्रेट, ये सारे सीरियस और हीनस ऑफ़ेन्सेस हैं जोकि उन के खिलाफ़ बनते हैं। उनको अभी तक गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया और इनके खिलाफ़ कार्यवाही क्यों नहीं की गई। जब ऐसी बात है, तो बी० आर० जी० की इन्कवाररी से क्या उम्मीद की जा सकती है कि सही सही तथ्यों का पता लगाया जाएगा। तो मेरे दो, तीन सवाल हैं। यह प्रारण सोशो और एकोनामिक प्रारण है और यह सामाजिक और धार्मिक प्रारण है, जिस को बड़ से समाप्त करना चाहिए। वहाँ जो म्यूनिसिपल मजदूरी मिलती है, उस का भी इस प्रश्न से सम्बन्ध है।

MR. DEPUTY-SPEAKER: You have put questions. Don't go into problems; problems can be discussed separately. This is Calling Attention.

श्री बसुना प्रसाद शास्त्री : मैं प्रश्न पूछ रहा हूँ। पहला मेरा प्रश्न यह है कि सामाजिक और धार्मिक समस्याओं का समाधान करने के लिए केन्द्रीय सरकार क्या करने जा रही है? क्या मेम्बरस ऑफ़ पार्लियामेंट की एक कमेटी इस काम के लिए नियुक्त की जाएगी जो इस तरह की सामाजिक और धार्मिक समस्याओं के समाधान के लिए कोई हल निकाले और उस के लिए सुझाव दे और उपाय बताए।

दूसरी बात यह है कि उन लोगों—एक्जीक्यूटिव मेजिस्ट्रेट, सिकल इंसपेक्टर, थानेदार, और के० बी० राव और दूसरे गुम्बों को गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया, इसका जवाब प्रायः दें।

तीसरा सवाल हमारा यह है कि इस सब के लिए कोई वूडिजियल इन्कवाररी कार्गिग की हो, इस के लिए प्रायः क्या करना चाहते हैं और बोधा प्रश्न यह है, जो सब ने पूछा है और जिस का उत्तर अभी तक नहीं प्राया है, कि जो लोग गोली से मारे गये, उन मृतकों के धार्मिकों को जीवित रखने के लिये कोई सहायता प्रायः देने जा रहे हैं या राज्य सरकार को इस तरह का निवन्ध या सुझाव प्रायः देने जा रहे हैं कि उन को उचित मुआवजा दिया जाए और तत्काल उन लोगों के खिलाफ़ सब कार्यवाही होनी चाहिये, इस के लिये प्रायः क्या करने जा रहे हैं।

SHRI H. M. PATEL: I am very sorry that the hon. Member is so much worked up on this issue. Undoubtedly tribal welfare is the responsibility of the Central Government and we will certainly discharge it. But this Cal-

ling Attention Notice is with reference to a particular matter. I will read it. It says:—

"The reported maltreatment to the representatives of the Peoples union of Civil Liberties from Delhi visiting Singhbhum district on Wednesday, the 7th March, 1979 to enquire into the complaints of violation of human rights of Adivasis of Singhbhum district."

We have given the report which was received from the State Government. It has been placed before the honourable House. All these points which the hon. Member has mentioned will certainly be brought to the notice of the State Government and we will also certainly pursue matters in which we are specially interested.

SHRI HARI VISHNU KAMATH (Hoshangabad): Sir, on a point of order.

I would like to invite your attention to Article 338 and 339 of the Constitution. It is not sufficient that a reference be made to the State Government only, because under Article 338, amended Article 338, there has recently been appointed a Commission for the Scheduled Castes and Scheduled Tribes. Under Article 338, there was a provision for 'Special Officer'; now, there is a Special Commission for the Scheduled Castes and Scheduled Tribes. Clause (2) of Article 338 now reads as follows, *mutatis mutandis*. This is the phrase to be used in this context, because 'Special Officer' is now replaced by 'Commission'. So it reads:

"It shall be the duty of the Commission to investigate all matters relating to the safeguards provided for the Scheduled Castes and Scheduled Tribes under this Constitution and report to the President . . ."

This is the relevant part of the Article, which is very appropriate in this context.

[Shri H. V. Kamath]

"...upon the working of those safeguards at such intervals as the President may direct, and the President shall cause all such reports to be laid before each House of Parliament."

Then clause (2) of Article 339 refers to the executive power of the Central Government. It reads:

"The executive power of the Union shall extend to the giving of direction to a State as to the drawing up and execution of schemes specified in the direction to be essential for the welfare of the Scheduled Tribes in the State."

The Minister must clarify whether this matter will be referred, besides the State Government, to the Scheduled Castes and Scheduled Tribes Commission also, and whether a report will be called for from that Commission and that report via the President will be laid on the Table of the House.

MR. DEPUTY-SPEAKER: I do not know whether you were here earlier when the Minister replied to this specific point. He said that the matter would be referred to the Commission, but at what stage he did not know. Whether it should be referred at this stage or later, that was the point, on which he could not say anything now.

श्री विनायक प्रसाद शर्मा : उपाध्यक्ष महोदय, यही तो हमारा रोना है। यही तो हमारा सबाल है कि इसे सेक्रेटरी कानून एवं सेक्रेटरी ट्राइबल कमीशन को क्यों नहीं भेजा गया ?

SHRI H. M. PATEL: First of all, I will repeat again that this calling attention notice was with reference to certain incidents which took place on the 7th and 8th March.

SHRI SURAJ BHAN (Ambala): You kindly read it fully; you have read half of it.... (Interruptions).

SHRI H. M. PATEL: I have said already that once it is established

that this particular incident followed upon various incidents that took place earlier, we will certainly take action. I said that we did not disown responsibility in so far as the tribals are concerned; their welfare is our responsibility.

So far as this Commission is concerned, it does not have to have any reference from us before it starts any enquiry; it can enquire itself. But now that these facts have come to our notice, we will ask the State Government to clarify the position and thereafter take whatever action is called for.

MR. DEPUTY-SPEAKER: I suggest that you send the entire proceedings of the House to the Commission.

SHRI H. M. PATEL: Certainly; I said that.

PROF. DILIP CHAKRAVARTY (Calcutta South): Mr. Deputy-Speaker, Sir, I am shocked to hear the legalistic approach made by the hon. Minister, Shri Patel. First of all, he said that the Ministry asked for reports from the State Government and the Minister of State laid down the narration of facts. If I have understood the meaning of this English language, this statement does not contain the narration of facts. It is a tissue of lies. It does not contain narration of facts. If what the Minister said subsequently is only the narration of the report from the State Government . . .

PROF. P. G. MAVALANKAR (Gandhinagar): The phrase "tissue of lies" is unparliamentary. You can say it is "terminological inexactitude"!

PROF. DILIP CHAKRAVARTY: It is a tissue of untruth. That is what I said. If it is just an analysis of the report received from the State Government, nothing can be said. Further, the Minister is under a misconception—possibly he has corrected himself by now—while making this legal-

istic approach and quoting from the Calling Attention notice. The Calling Attention says:

"to call the attention of the Minister of Home Affairs to the reported maltreatment to the representatives of the People's Union of Civil Liberties from Delhi visiting Singhbhum district on Wednesday, the 7th March, 1979 to enquire into the complaints of violation of human rights of Adivasis of Singhbhum district and widespread resentment among the people."

Now, to go into the genesis of the whole trouble, I draw your attention to this, i.e. to a statement made by an hon. Member under rule 377 as early as on 22nd December 1978.....

12.57 hrs.

(MR. SPEAKER in the Chair)

Sir, I have just begun. It is regarding the happenings against Adivasis, tortures committed against them and the SCs and STs in Chaibasa, headquarters of Singhbhum district and in the Chhota Nagpur division. What is the problem? There, the poor landless labourers were terrorized by the big landlords, who apparently had the backing of the Police, only because they were agitating for the payment of the prescribed minimum wages for farm labourers, and for a more humane treatment. They were also agitating for the replacement of sal tree plantations by teak plantations, on the ground that the seeds of the former, had food value, and were a source of subsistence for them. The team of the People's Union of Civil Liberties went to Ichahatu, Sarangda and Lonju. At Lonju, they were lathi-charged by the Police; and at Barhagora, the police had resorted to firing.

In the background of all these happenings, the team thought it necessary to go there. It moved in different areas. They met the district officers at Chaibasa on 3rd March. They met the S.P. the forest officer, and also a

cross-section of the people. However, the Deputy Commissioner was not available. So, they could not meet him. But the administration had information. The Minister of State for Home Affairs may kindly note this. They were beaten 4 days after this. They were beaten by the police at Barhagora. The State Government is reported to have made a statement. This is the statement before us: "There was no advance information about their visit to this area."

13 hrs.

Will the Minister take it up with the State Government, for sending a report which is not corroborated by facts? I can quote further. I have the letters. After the first happening, Shri Govinda Mukhoty wrote a letter as early as on 24th December, to the Chief Minister of Bihar. In that letter, Shri Gobinda Mukhoty says:

"Recently, atrocities in Bajitpur in Bihar, where hearth and home of 169 families have been completely wiped off by 400 musclemen at the instance of a landlord, have led to lot of anxiety amongst the thinking people of this country....."

"It is inconceivable as to how miscreants went on demolishing hut after hut for eight hours, without being checkmated by the police. It is also surprising that only after 24 hours of the incident, the Superintendent of Police came to enquire about the incident. If these incidents occur, public will soon lose all confidence in the Government. As a matter of fact, if such incidents can occur in a State, the State Government ought to take responsibility and resign. But, then, we, in this country, seem to be oblivious to the sufferings of the common people."

I can quote from the letter written to the Chief Minister of Bihar.

MR. SPEAKER: Let us come to the question.

PROF. DILIP CHAKRAVARTY: It says:

"This incident has so shocked the conscience of the people that over 2000 students/teachers and karamcharis of Delhi University, Jawaharlal Nehru University, Institute of Economic Growth and Indian Institute of Public Administration are sending a memorandum to you."

I am not going to read the contents to save time. Then the Chief Minister of Bihar gave a reply. This was dated 21-1-1979. I shall read a small portion from the Chief Minister's letter. You can make it a part of the proceedings, Shri Karpoori Thakur says:

"The incident of loot and assault, which took place on 15-11-1978 in the village Bajatpur, Distt Begusarai is very unfortunate/sad event. About this occurrence, cases have been registered, etc."

He also wrote about the accused persons. He said:

"All accused persons, except seven persons, have been arrested."

I ask whether all these seven persons were the real culprits. That is why they escaped the arrest. This happens all over the country.

MR. SPEAKER: You cannot make a speech. There is a limit. After all, it is a calling attention.

PROF. DILIP CHAKRAVARTY: On 29th January, 1979, Gobinda Mukhoty wrote to Shri Karpoori Thakur about the coming visit of the team. Now here it is astounding that in this statement some unfortunate wrong things have been made out. The statement says that there was no advance information about the visit of the team. I am carrying the original letter of the Chief Minister with me to show that he was informed about it and there was an appointment made with the Chief Minister of Bihar at Patna on

the 8th of March. If there was no beating on the 7th, they would have met the Chief Minister on the 8th at Patna and submitted their report to him. An attempt has been made through this note to show that members of the team were accompanied by naxalites. I am asking this question through you. Now the Prime Minister is also here. Suppose I am a naxalite by a political faith, is it a crime? Shall I be arrested for that? I asked this specific question whether there was any case, whether there was any arrest warrant against those so-called naxalites. They are not naxalites. One of them was engaged in Kisan samiti activities. There was no case.

MR. SPEAKER: Please come to the question.

PROF. DILIP CHAKRAVARTY: I am dealing with the report and on the basis of it, I am putting a question. The Assistant Sub-Inspector took them to Barhagora Police Station. I heard a tape recording brought to me by the team where it was made out that one of them was known to Choudhuri Charan Singh.

इन तो इस इलाके के मालिक हैं, वरन सिंह हमारा क्या करेगा।

These types of atrocious statements were made by ordinary police officers and Assistant Sub-Inspectors of Police. Does the Minister think that merely by suspending such police officers things will be all right?

MR. SPEAKER: I have to stop recording of your speech. I am going to stop recording of your speech.

PROF. DILIP CHAKRAVARTY: My third question is this. Whether a comprehensive enquiry will be undertaken and whether this House will be reported about the contents of the same and the steps taken.

की विभाजक प्रसवदायक : वहाँ के पुलिस अधिकारी कहते हैं हम तो मोरपत्ती बार्ड की नहीं जानते हैं, हम तो चौकरी बरख सिंह को नहीं जानते हैं।

PROF. DILIP CHAKRAVARTY:

The person who offered them tea was actually forced by the police to submit a complaint, under coercion, against his guests. Is it not an offence to lodge a statement which is not based on facts? What steps have been taken or proposed to be taken against such false complaint? Did the guests snatch their cups of tea offered by the host? Is it a punishable offence? One more question.

MR. SPEAKER: No further question. I am not allowing; there will be no recording. This is not a cross-examination. Only one question is allowed under the rules; I have allowed three questions.

PROF. DILIP CHAKRAVARTY: I want to add one more thing.

MR. SPEAKER: You may want to add many more things but nothing will go on record; I am not allowing. The hon. Minister.

SHRI H. M. PATEL: I should like to refer to two points. When I say that I am placing the facts before this House, I said also, facts as reported to me by the state government. Therefore, that is clear. So far as other points are concerned, again I reported whatever was communicated by the State government. As regards other questions, question underlying this incident, I have already said that we will go into them and

make a thorough enquiry; we will ask the state government to do this. To the extent tribal welfare is concerned—tribals are involved in this matter; adivasi interests are involved—we will also go into it, either directly or through a commission.

COMMITTEE ON THE WELFARE OF SCHEDULED CASTES AND SCHEDULED TRIBES

TWENTY-SIXTH AND TWENTY-SEVENTH REPORTS

SHRI SURAJ BHAN (Ainbala): I beg to present the following Reports (English and Hindi versions) of the Committee on the Welfare of Scheduled Castes and Scheduled Tribes (1978-79):—

(1) Twenty-sixth Report on Action taken by Government on the recommendations contained in the Twentieth Report of the Committee on the Ministry of Information and Broadcasting—Reservations for, and employment of, Scheduled Castes and Scheduled Tribes in All India Radio.

(2) Twenty-seventh Report on Action taken by Government on the recommendations contained in the Eleventh Report of the Committee on the Ministry of Home Affairs—Reservations for, and Employment of, Scheduled Castes and Scheduled Tribes in the Delhi Electric Supply Undertaking.